The Period of illegal Currency and India
(अवैधानिक मुद्रा का दौर और भारत)

Dr. Dharmendra Kumar Singh
(डा धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सीताराम सिंह इण्टर कालेज
बाबूगंज, इलाहाबाद

Received: March 1, 2018 Accepted: April 02, 2018

आभासी मुद्रा का लगातार बढ़ रहा प्रचलन 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। आभासी मुद्रा को लेकर हाल ही में आर्थिक मामलों ने यह आदेश पारित किया है कि लोग बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो– करेंसी में निवेश करने से बचें। क्रिप्टो– करेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर–टू–पीयर कैश सिस्टम है। क्रिप्टो–करेंसी को डिजिटल वालेट में ही रखा जा सकता है। दरअसल, क्रिप्टो–करेंसी के इस्तेमाल के लिये बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की जरूरत नहीं होती है।

क्रिप्टो–करेंसी मुख्य रुप से दो प्रकार की होती है। फिएट और नॉन–फिएट क्रिप्टो–करेंसी ''नॉन–फिएट'' क्रिप्टो–करेंसी को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ–साथ सरकारें भी समय–समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती हैं। एक 'नॉन–फिएट' क्रिप्टो–करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एक निजी क्रिप्टो–करेंसी है। जबकि 'फिएट क्रिप्टो–करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ''नॉन–फिएट'' क्रिप्टो–करेंसी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं और यह तकनीकी उन्नयन विनाशकारी साबित हो सकता है। यदि भातरीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई आभासी मुद्रा जारी की जाती है, तो उसे फ़िएट क्रिप्टो–करेंसी कहा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सभी क्रिप्टो–करेंसी बिटकॉइन नहीं है, जबकि सभी बिटकॉइन क्रिप्टो–करेंसी हैं। बिटकॉइन, एथ्रॉम और रिप्पल कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो–करेंसी हैं।

क्रिप्टो–करेंसी की सम्पूर्ण व्यवस्था के ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा कमजोर हो जाती है और इसके हैंक होने का खतरा बना रहा है। क्रिप्टो–करेंसी की सबसे बड़ी समस्या है इसका ऑनलाइन होना और यही कारण है कि क्रिप्टो–करेंसी को एक असुरक्षित मुद्रा माना जा रहा है। यह 'मुख्य वित्तीय सिस्टम' और 'बैकिंग प्रणाली' से बाहर रहकर काम करती है। यही कारण है कि इसके स्रोत और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं। इस डिजिटल मुद्रा को फ्रॉड, हवाला मनी और आतंकी गतिविधियों को पोषित करने वाली मुद्रा के रुप में संबोधित किया जाता रहा है। क्रिप्टो–करेंसी से संबंधित एक बड़ी समस्या इसके नियंत्रण एवं प्रबंधन की भी है। भारत जैसे कई देशों ने अभी तक इसे मुद्रा के रुप में स्वीकृति प्रदान नहीं की है, ऐसे में इसका प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। आर्थिक जानकारों का भी मानना है कि इसकी तकनीकी जानकारी रखे बिना इसमें निवेश करने के भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं। गौरतलब है कि प्रत्येक बिटकॉइन लेन–देन के लिये लगभग 237 किलोवाट बिजली की खपत होती है और इससे प्रतिघंटा लगभग 92 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है।

इन तमाम चिंताओं के बावजूद बिटकॉइन और एथ्रॉम जैसी क्रिप्टो–करेंसिया लगातार लोकप्रिय होती जा रही हैं और सरकारें चाहकर भी इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं। विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकों को यह महसूस होने लगा है कि क्रिप्टो–करेंसी को नियंत्रित करने की कोशिश निरर्थक है और वे स्वयं के क्रिप्टो–करेंसी जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि नाम नामित ''लक्ष्मी'' होगा। भारत की यह अपनी क्रिप्टो–करेंसी फिएट क्रिप्टो–करेंसी के नाम से जानी जाएगी।

देश में बिटकॉइन की स्थिति तय करने के लिये वित्त मंत्रालय ने एक अंतर–अनुशासनात्मक समिति गठित की है, जो भारत में बिटकॉइन के भविष्य की दशा–दिशा पर सुझाव देगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में आयकर विभाग ने देश के बड़े बिटकॉइन एक्सचेंजों में टैक्स चोरी की संभावनाओं के मद्देनजर सर्वे किये थे और इसके मद्देनजर सरकार द्वारा बिटकॉइन पर एक अन्य समिति का गठन किया है। रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी.पी. कानूनगों और सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी वित्त मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति में शमिल हैं। हालांकि, इससे पहले मार्च 2017 में बिटकॉइन पर एक समिति बनाई गई थी, जो कोई ठोस सुझाव देने में असफल रही थी। वर्ष 2007 में सुभाष चंद्रा ने आईसीएल की शुरुआत की थी। यहाँ भी स्थिति लगभग बिटकॉइन जैसी ही थी। देश में क्रिकेट संबंधी गतिविधियों की विधिवत कर्त्ता–धर्त्ता बीसीसीआई चाहकर भी इसे बंद नहीं करा पाई। ऐसे में बीसीसीआई ने आईपीएल के नाम से खुद की अपनी टी–20 लीग शुरू की और आईसीएल खत्म हो गया। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को भी यही करना चाहिये, उन्हें स्वयं की अपनी क्रिप्टो–करेंसी जारी करनी चाहिये। भारत इसकी कवायद आंरभ भी कर चुका है।

यदि देश के सेंट्रल बैंक द्वारा खुद की वर्चुअल करेंसी जारी की जाती है तो सबसे पहले डबल स्पेंडिगम की समस्या से निपटना होगा। दरअसल, क्रिप्टो–करेंसी एक डिजिटल करेंसी होगी और यह देखते हुए कि जो कुछ भी डिजिटल है उसे आसानी से कॉपी किया जा सकता है। ऐसे में कोई किसी को मुद्रा ही इकाई के दुबारा इस्तेमाल से कैसे रोक सकता है? डबल स्पेंडिग की समस्या से निपटने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी इसे हैक–प्रूफ बनाने हेतु अतिरिक्त करने होंगे। यदि क्रिप्टों करेंसी को एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रुप में अधिकृत कर वैधानिकता प्रदान की गई तो इसके विनियमन का दायित्व आरबीआई को निभागा होगा। पूंजी लाभ और व्यापारिक लेन–देन पर टैक्स की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही विदेशो में होने वाले भुगतान को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के दायरे में लाना होगा। क्रिप्टो–करेंसी का विनियमन उपभोक्ता संरक्षण को मजबूती प्रदान करेगा।

क्रिप्टो–करेंसी का इस्तेमाल सामाजिक विकास के लिये किया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ सावधानियाँ बरतने की भी ज़रूरत है। किस विशेष सामाजिक विकास के कार्य संपूर्ण हो जाने और विशेषज्ञों द्वारा इसकी सम्पूर्णता की जाँच के उपरांत गैर–लाभकारी संगठनों एवं निजी संगठनों को क्रिप्टो–करेंसी दिया जा सकता है। इससे गैर–लाभकारी संगठनों के बीच सामाजिक विकास के लिये भागीदारी और प्रतिस्पर्द्धा में बढ़ोत्तरी होगी। यदि सामाजिक विकास के क्षेत्र में भागीदारी और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है, तो यह विदेशी निवेशकों के साथ–साथ कॉपोरेट संगठनों को आकर्षित कर सकेगा। अतः क्रिप्टो–करेंसी का इस्तेमाल सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अलावा नवाचारों को भी बढ़ावा होगा।

भारत में सबसे ज्यादा नकदी संचालन में है, 2014 में यह जीडीपी की 12.42 प्रतिशत थी, जबकि चीन और ब्राज़ील के लिये ये आँकड़े क्रमशः 9.47 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत थे। गौरतलब है कि नकद संचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों का सालाना खर्च 21,000 करोड़ रूपए आता है। ऐसे में क्रिप्टो–करेंसी को बढ़ावा देना कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्रिप्टो–करेंसी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी अहम् साबित हो सकता है। विदित हो कि वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण बैंकों का दिवालिया हो जाना था और भविष्य में भी एका हो सकता है। इन परिस्थितियों में यदि बैंकिंग व्यवस्था से अलग लेकिन एक विनियमित मुद्रा जैसे की फिएट क्रिप्टो–करेंसी अहम् साबित हो सकती है।

निष्कर्ष–

क्रिप्टो–करेंसी की आगे की सफलता इसके विनियामक ढाँचे के स्वरुप पर निर्भर करता है। दरअसल विभिन्न देशों ने इस नवाचार के प्रति अलग–अलग दृष्टिकोण अपनाया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले वेनेजुएला ने पेट्रो नामक क्रिप्टो–करेंसी का प्रचालन आरंभ किया था, लेकिन हाल ही में वहाँ की संसद ने पेट्रो को अवैध घोषित कर दिया है। यही कारण है कि इस संबंध में नियामकीय अनिश्चिता का माहौल बना हुआ है। अतः सरकार को आतंक के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी में क्रिप्टो–करेंसी के संभावित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनानी होंगी।

Reference

1. Sethi TT , Monetary Economics, Publishers LNA-17, 1974.
2. Dutt & Sundhram, Indian Economy, 70th Edition, 2013.
3. Singh Ramesh, Indian Economy, Publisher-Mcgraw hill Education.
4. www.indiawaterportal.org.
5. www.drishtiias.com.

Failure is the opportunity to begin again, more intelligently.

~ Henry Ford